भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3592**

(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/6 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**आईएफसी द्वारा सस्ते हरित गृहों की वित्त व्यवस्था**

3592. श्री एन॰ गोकुलकृष्णनः

 क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आईएफसी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेन्स के साथ मिलकर 800 मिलियन अमरीकी डॉलर से संयुक्त पूल के सृजन सहित लगभग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की नयी वित्त व्यवस्था के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आईएफसी ने एचडीएफसी को पिछले वर्ष सस्ते मकानों के निर्माण की वित्त व्यवस्था में सहयोग दिया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

**(क) और (ख):** अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍त निगम (आईएफसी) ने पीएनबी आवास वित्‍त निगम (पीएनबीएचएफएल) के समतुल्‍य 400 मिलियन यूएस$ तक के रूपया मसाला बांड को विदेशों में पहली बार जारी किए जाने के संचालन की सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की है। अपने स्‍वयं के खाते पर 150 मिलियन यूएस$ के मसाला बांड को खरीदने के अलावा, पीएनबीएचएफएल द्वारा बाजार से 250 मिलियन यूएस$ की पूंजी जुटाने की सुविधा की भी परिकल्‍पना की गई है। पीएनबीएचएफएल अपने स्‍वयं के संसाधनों से भारत में सस्‍ते आवास तथा हरित क्षेत्र के लिए 800 मिलियन यूएस$ के कुल पूल के निर्माण हेतु 400 मिलियन यूएस$ तक की अतिरिक्‍त राशि प्रदान करेगा।

**(ग) और (घ):** वर्ष 2017 में आईएफसी ने एचडीएफसी लि. द्वारा जारी सूचीबद्ध 5 वर्षीय भारतीय रूपया(आईएनआर) मसाला बांड के अभिदान के माध्‍यम से आवास विकास वित्‍त निगम (एचडीएफसी) में 200 मिलियन यूएस$ का निवेश किया था।

\*\*\*\*\*